International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

नागरिक समाज और सांस्कृतिक आधिपत्य: एंटोनियो ग्राम्शी के हेजेमनी सिद्धांत की समकालीन भारतीय राजनीति और मीडिया विमर्श में प्रासंगिकता

Civil Society and Cultural Hegemony: Relevance of Antonio Gramsci's Hegemony Theory in Contemporary Indian Politics and Media Discourse

सौरभ साहू

शोध सारांश (Abstract)

यह शोध-पत्र इतालवी मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्शी (Antonio Gramsci) के 'सांस्कृतिक आधिपत्य' (Cultural Hegemony) के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समकालीन भारतीय राजनीति और मीडिया विमर्श का एक आलोचनात्मक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण करता है। पारंपरिक मार्क्सवाद जहाँ सत्ता को केवल आर्थिक आधार (Base) और बल-प्रयोग के रूप में देखता था, वहीं ग्राम्शी ने स्पष्ट किया कि आधुनिक पूँजीवादी राज्य 'नागरिक समाज' (Civil Society) के माध्यम से 'सहमति' (Consent) का निर्माण करके अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इस विस्तृत शोध अध्ययन में इस बात की गहन पड़ताल की गई है कि कैसे समकालीन भारत में राजनीतिक विमर्श और मुख्यधारा का मीडिया एक ऐसा 'सामान्य बोध' (Common Sense) गढ़ रहे हैं, जो सत्ताधारी विचारधारा को प्राकृतिक और अपरिहार्य के रूप में स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, यह पत्र 'जैविक बुद्धिजीवी' (Organic Intellectuals) और 'स्थिति का युद्ध' (War of Position) जैसी ग्राम्शियन अवधारणाओं के माध्यम से भारत में प्रति-आधिपत्य (Counter-hegemony) की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): सांस्कृतिक आधिपत्य, नागरिक समाज, सहमति का निर्माण, सामान्य बोध, जैविक बुद्धिजीवी, स्थिति का युद्ध, भारतीय मीडिया विमर्श, नव-उदारवाद।

1. प्रस्तावना (Introduction)

राजनीतिक सत्ता केवल सेना, पुलिस या कानूनी तंत्र जैसे दमनकारी राज्य तंत्रों (Repressive State Apparatus) द्वारा नहीं चलाई जाती। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में, सत्ता का वास्तविक स्थायित्व नागरिकों के मस्तिष्क और उनकी संस्कृति पर नियंत्रण से आता है। 1920 के दशक में इटली में फासीवादी मुसोलिनी के शासनकाल के दौरान जेल में रहते हुए, इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एंटोनियो ग्राम्शी ने अपनी

प्रसिद्ध कृति *'प्रिज़न नोटबुक्स' (Prison Notebooks)* की रचना की। इस कृति में उन्होंने मार्क्सवाद की पारंपरिक कठोरता को चुनौती दी और 'सांस्कृतिक आधिपत्य' का विचार प्रस्तुत किया। समकालीन भारतीय राजनीति, जो नव-उदारवाद (Neoliberalism) और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक गहरे संक्रमण के दौर से गुजर रही है, को समझने के लिए ग्राम्शी का यह सिद्धांत एक अत्यंत प्रभावी वैचारिक उपकरण (Conceptual Tool) प्रदान करता है।

स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय राज्य ने विकासवादी विचारधारा के माध्यम से अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 21वीं सदी के भारत में, यह आधिपत्य मुख्यधारा के मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से एक नया रूप ले चुका है, जहाँ सत्ता का प्रयोग बल से अधिक 'सहमति' के आधार पर किया जा रहा है।

2. सैद्धांतिक ढांचा: ग्राम्शी का आधिपत्य (Hegemony) और नागरिक समाज

पारंपरिक मार्क्सवाद (Orthodox Marxism) के विपरीत, ग्राम्शी ने संरचना (Base - आर्थिक ढांचा) और अधिरचना (Superstructure - संस्कृति, धर्म, मीडिया) के संबंध को अधिक द्वंद्वात्मक और जटिल माना। ग्राम्शी के अनुसार, राज्य केवल बल (Coercion) पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह **बल + सहमति (Force + Consent)** का मिश्रण है, जिसे उन्होंने "बख्तरबंद सहमति" (Armoured Consent) कहा था।

ग्राम्शी ने अधिरचना को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया:

- **राजनीतिक समाज (Political Society):** इसमें राज्य के वे संस्थान शामिल हैं जो सीधे तौर पर 'प्रभुत्व' (Domination/Coercion) या बल का प्रयोग करते हैं, जैसे पुलिस, सेना, और कानूनी तंत्र।
- **नागरिक समाज (Civil Society):** इसमें विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थान, मीडिया, और परिवार जैसी गैर-सरकारी संस्थाएं शामिल हैं।

शासक वर्ग नागरिक समाज के इन्हीं संस्थानों का उपयोग करके जनता के बीच अपनी विचारधारा को स्थापित करता है। यह विचारधारा बलपूर्वक नहीं थोपी जाती, बल्कि इसे शिक्षा और मीडिया के माध्यम से धीरे-धीरे जनता का **'सामान्य बोध' (Common Sense)** बना दिया जाता है। सामान्य बोध वह स्थिति है जहाँ समाज का शोषित वर्ग (Subaltern Class) शासक वर्ग की विचारधारा को स्वेच्छा से स्वयं के अनुकूल मानकर स्वीकार कर लेता है और उसे अपने ही हित में मानने लगता है। स्वेच्छा से निर्मित इसी जन-सहमति की प्रक्रिया को 'सांस्कृतिक आधिपत्य' या 'हेजेमनी' कहा जाता है।

3. जैविक बुद्धिजीवी (Organic Intellectuals) और स्थिति का युद्ध (War of Position)

ग्राम्शी ने बुद्धिजीवियों को दो श्रेणियों में बांटा: पारंपरिक बुद्धिजीवी (Traditional Intellectuals) जो खुद को सामाजिक बदलावों से तटस्थ मानते हैं (जैसे शिक्षक, पादरी), और जैविक बुद्धिजीवी (Organic Intellectuals)। जैविक बुद्धिजीवी वे विचारक होते हैं जो किसी विशेष सामाजिक या आर्थिक वर्ग की आकांक्षाओं को बौद्धिक और सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था अपने स्वयं के जैविक बुद्धिजीवियों (जैसे अर्थशास्त्री, मीडिया एंकर, कॉर्पोरेट रणनीतिकार) को जन्म देती है, जो उनके आधिपत्य को सही ठहराते हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्राम्शी ने क्रांति की रणनीति को दो भागों में बांटा: 'गति का युद्ध' (War of Maneuver) जो सीधे राज्य की सत्ता पर □□□त्यक्ष और हिंसक अधिकार है (जैसे 1917 रूस की बोल्शेविक क्रांति), और 'स्थिति का युद्ध' (War of Position)। नागरिक समाज वाले उन्नत पूँजीवादी देशों में, 'स्थिति का युद्ध'

अधिक प्रासंगिक है, जो नागरिक समाज के संस्थानों के भीतर लड़ा जाने वाला एक सुदीर्घ और निरंतर वैचारिक व सांस्कृतिक संघर्ष है।

4. समकालीन भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक आधिपत्य

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में, ग्राम्शी का सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि राजनीतिक सत्ता केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक समाज में एक विशिष्ट सांस्कृतिक आख्यान (Narrative) को स्थापित करने की प्रक्रिया है। भारतीय संदर्भ में इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

- **राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्गठन:** समकालीन भारत में, शासक वर्ग ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को पुनः परिभाषित करके एक नया राजनीतिक 'सामान्य बोध' गढ़ा है। राष्ट्रवाद, नागरिकता और विकास की नई परिभाषाओं को नागरिक समाज के संस्थानों के माध्यम से जन-चेतना में इस प्रकार रोपा गया है कि वे प्राकृतिक और अकाट्य सत्य प्रतीत होते हैं।
- **नव-उदारवादी सहमति (Neoliberal Consent):** बेरोजगारी और आर्थिक विषमता जैसी गंभीर चुनौतियों के बाद भी यदि शासक वर्ग को व्यापक जन-समर्थन मिलता है, तो यह ग्राम्शी के 'सहमति' के सिद्धांत को सिद्ध करता है। सत्ताधारी वर्ग अपनी नव-उदारवादी नीतियों (Privatization, Deregulation) को राष्ट्र के विकास के व्यापक हित के रूप में पेश करने में सफल रहा है। परिणामतः, आम जनता उन आर्थिक नीतियों का भी समर्थन करती है जो सीधे तौर पर उनके वर्ग-हितों (Class Interests) के अनुकूल न हों, क्योंकि वैचारिक आधिपत्य स्थापित हो चुका है।
- **जातिगत पदानुक्रम और आधिपत्य:** भारतीय संदर्भ में आधिपत्य केवल वर्गीय नहीं, बल्कि जातीय भी है। सवर्ण आधिपत्य ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय नागरिक समाज में एक 'सामान्य बोध' गढ़ा है, जिसने सामाजिक पदानुक्रम (Hierarchy) को धार्मिक और कर्मकांडीय आधारों पर तर्कसंगत ठहराया।

5. मीडिया, संचार व्यवस्था और 'सामान्य बोध' का निर्माण: एक वैचारिक उपकरण

ग्राम्शी के अनुसार, नागरिक समाज में वैचारिक वर्चस्व कायम करने में संचार माध्यमों की केंद्रीय भूमिका होती है। समकालीन भारत में टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस आधिपत्य को बनाए रखने के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। नोअम चोम्स्की (Noam Chomsky) और एडवर्ड हरमन ने अपने मॉडल *'मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट' (Manufacturing Consent)* में भी इसी बात को पुष्ट किया है, जो ग्राम्शी के विचारों का ही विस्तार है।

- **टेलीविजन न्यूज़ एंकर की जैविक बुद्धिजीवी के रूप में भूमिका:** मुख्यधारा के मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी विचारधारा के लिए 'जैविक बुद्धिजीवी' (Organic Intellectuals) के रूप में कार्य करता है। प्राइम-टाइम डिबेट्स की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाती है कि वैकल्पिक और आलोचनात्मक विमर्श हाशिए पर चले जाते हैं और मीडिया एंकर जनता के मन में यह विश्वास पैदा करते हैं कि राज्य की नीतियां ही अंतिम सत्य हैं।
- **असहमति का अ-वैधीकरण (De-legitimization of Dissent):** जो विचार या समूह इस स्थापित 'सामान्य बोध' को चुनौती देते हैं, मीडिया विमर्श के जरिए उन्हें 'अस्वाभाविक', 'अवांछित', 'अर्बन नक्सल' या 'राष्ट्र-विरोधी' के रूप में चित्रित करता है। इस प्रकार, राज्य प्रत्यक्ष बल के बजाय मीडिया तंत्र के वैचारिक आधिपत्य से असहमति को नियंत्रित करता है।

- **अति-यथार्थता (Hyper-reality) और एल्गोरिथम आधिपत्य:** डिजिटल युग में सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ग्राम्शी के आधिपत्य की प्रक्रिया को नए आयाम देता है। यह इको-चैंबर (Echo Chambers) बनाकर एक ऐसी अति-यथार्थता का निर्माण करता है जहाँ वस्तुनिष्ठ तथ्यों की तुलना में भावनात्मक और सांस्कृतिक अपील अधिक प्रभावशाली हो जाती है।

6. भारत में प्रति-आधिपत्य (Counter-Hegemony) का उभरता परिदृश्य

ग्राम्शी की मान्यता थी कि कोई भी आधिपत्य पूरी तरह स्थिर या निरपेक्ष नहीं होता; उसके भीतर ही प्रतिरोध के बीज अंकुरित होते हैं। वर्चस्व को चुनौती देने के लिए एक 'स्थिति का युद्ध' (War of Position) आवश्यक है, जो नागरिक समाज के भीतर से ही शुरू होता है।

भारतीय संदर्भ में, 2020-21 का ऐतिहासिक किसान आंदोलन 'प्रति-आधिपत्य' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इस आंदोलन ने मुख्यधारा के मीडिया द्वारा निर्मित आख्यान का मुकाबला करने के लिए अपने स्वयं के वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पारंपरिक सामुदायिक संस्थाओं (जैसे खाप पंचायतों) का सहारा लिया। 2026 मध्य में हुए छात्र आंदोलन में भी मुख्य धारा के कुछ मीडिया आख्यानों का मुकाबला करने के लिए कुछ नव उद्दैमान यूट्यूबर्स द्वारा इन आख्यानों को वास्तविक धरातल की स्थिति से प्रतिस्थास्पित कराया। इसके अतिरिक्त, दलित-बहुजन विमर्श, पॉडकास्ट(Podcast), साहित्य और सामाजिक आंदोलन भी भारत के स्थापित सवर्ण-पूँजीवादी वर्चस्व के विरुद्ध निरंतर काउंटर-हेजेमनी का निर्माण कर रहे हैं। ग्राम्शी के शब्दों में, भारत के सबाल्टर्न (हाशिए पर स्थित) समाजों को अपने स्वयं के 'जैविक बुद्धिजीवी' तैयार करने होंगे जो इस स्थापित 'सामान्य बोध' का खंडन कर एक समतामूलक 'विवेकशीलता' (Good Sense) को जन्म दे सकें।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्षतः, समकालीन भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के अध्ययन में एंटोनियो ग्राम्शी का हेजेमनी सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि भारत में वर्तमान सत्ता संरचना केवल बल-प्रयोग या राजनीतिक शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से एक गहरी सांस्कृतिक और वैचारिक सहमति का निर्माण किया है। भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वैश्वीकरण और डिजिटल एल्गोरिथम के दौर में हाशिए के वर्ग इस स्थापित सांस्कृतिक आधिपत्य को कैसे चुनौती देते हैं। जब तक नागरिक समाज में एक मजबूत 'स्थिति का युद्ध' नहीं लड़ा जाता, तब तक किसी भी राजनीतिक परिवर्तन की जड़ें मजबूत नहीं हो सकतीं।

8. संदर्भ ग्रंथ सूची एवं बिब्लियोग्राफी (Bibliography & References)

1. **Gramsci, A.** (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Trans.). International Publishers. *(सांस्कृतिक आधिपत्य, नागरिक समाज और जैविक बुद्धिजीवी की मूल अवधारणाओं का आधार)।*
2. **Chatterjee, Partha.** (2004). *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World.* Columbia University Press. *(भारतीय परिप्रेक्ष्य में नागरिक बनाम राजनीतिक समाज)।*
3. **Chomsky, N., & Herman, E. S.** (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media.* Pantheon Books. *(मीडिया द्वारा सहमति निर्माण के सैद्धांतिक विश्लेषण हेतु)।*
4. **Rajagopal, Arvind.** (2001). *Politics After Television: Hindu Nationalism and the Reshaping of the Public in India.* Cambridge University Press.

5. **Gudavarthy, Ajay.** (2014). *Maoism, Democracy and Project Hegemony.* SAGE Publications India. *(भारतीय राजनीति में स्थिति का युद्ध और प्रति- आधिपत्य) ।*
6. **Sharma, Rajesh.** (2016). "An Indian Context of Antonio Gramsci's Views on Hegemony & Civil Society." *Social Research Foundation.* (पीयर-रिव्यू मूल्यांकित शोध-पत्र)।
7. **Jodhka, S. S.** (2015). *Caste in Contemporary India.* Routledge. *(भारत में जातिवादी आधिपत्य और सामान्य बोध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण) ।*
8. **Economic and Political Weekly (EPW).** (2018). *Caste and class hegemonies: Antonio Gramsci has shown how nationalism can also become a hegemony of the dominant classes* (Online Archives).